Test
Cloud

Daily
करेंट अफेयर्स

15 अगस्त 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. CM स्टालिन ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर-घर राशन पहुंचाने के लिए 'थायमानवर योजना' का शुभारंभ किया।

13 अगस्त 2025 को, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री थायुमानवर योजना शुरू की, जिससे वरिष्ठ नागरिकों (70 वर्ष से अधिक) और विकलांग व्यक्तियों (PwD) को आवश्यक राशन वस्तुओं की घर-द्वार पर डिलीवरी सुनिश्चित हुई, जिससे कमजोर आबादी के लिए अंतिम छोर तक पहुंच की बाधाओं का समाधान हुआ।

- **इस योजना से राज्य भर में लगभग 21.7 लाख लोगों को लाभ होगा। इनमें 20.42 लाख वरिष्ठ नागरिक और 1.27 लाख दिव्यांगजन शामिल हैं, जिनकी पहचान 16.73 लाख राशन कार्डों के माध्यम से की गई है।**

- **चावल, चीनी, गेहूँ, पामोलीन तेल और तूअर दाल जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का वितरण हर महीने के दूसरे शनिवार और रविवार को होगा। राज्य का सहकारिता विभाग इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटों, ई-पीओएस मशीनों और आधार-आधारित प्रमाणीकरण से लैस मिनी वैन के माध्यम से रसद का प्रबंधन करेगा।**

Key Points:-

(i) मुख्यमंत्री स्टालिन ने चेन्नई के टोंडियारपेट और अन्नाई सत्य नगर जैसे इलाकों में लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से राशन सामग्री वितरित की, जबकि उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेपक और ट्रिप्लीकेन में वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाई।

(ii) कोयम्बटूर में, वर्चुअल लॉन्च में 1,401 राशन दुकानों से जुड़े 89,023 लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने के लिए 1,235 वितरण टीमें जुटीं, जिससे राज्य भर में योजना की व्यापक पहुंच में योगदान मिला।

(iii) "अंतिम छोर तक पहुँचने की बाधा" से निपटने के लिए एक कदम के रूप में तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य वंचित नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखना है। तमिलनाडु ने लाभों का निर्बाध और समावेशी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग ₹30-36 करोड़ आवंटित किए हैं।

2. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने PMFBY के तहत किसानों को 3,200 करोड़ रुपये जारी किए।

अगस्त 2025 में, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 35 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 3,200 करोड़ रुपये की पहली बीमा किस्त के डिजिटल हस्तांतरण की घोषणा की। राजस्थान के झुंझुनू में आयोजित इस कार्यक्रम में इस योजना की नौवीं वर्षगांठ मनाई गई।

• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में डिजिटल हस्तांतरण किया गया, जिससे वितरण में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हुई। यह पहली किस्त लगभग 8,000 करोड़ रुपये की एक बड़ी राशि का हिस्सा है, जो PMFBY के तहत आगामी किश्तों में वितरित की जाएगी।

• राज्यवार दावा वितरण के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपये, राजस्थान के किसानों को 1,121 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। अन्य राज्यों के किसानों को सामूहिक रूप से 773 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो बीमा लाभ की व्यापक भौगोलिक पहुँच को दर्शाता है।

• खरीफ 2025 सीजन से, यह योजना दावा निपटान पर सख्त समयसीमा लागू करेगी, जिसमें राज्यों या बीमा कंपनियों द्वारा की गई देरी के लिए 12% जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा, जिसका उद्देश्य दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है।

Key Points:-

(i) भारत सरकार द्वारा 18 फरवरी, 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य सूखा, बाढ़, चक्रवात, कीटों और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल की बर्बादी से होने वाले वित्तीय नुकसान से किसानों की रक्षा करना है। यह प्रमुख योजना किसानों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ जोखिम न्यूनीकरण को भी जोड़ती है।

(ii) जनवरी 2025 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि तक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के साथ PMFBY को जारी रखने की मंजूरी दी, जिससे देश भर में व्यापक फसल बीमा कवरेज सुनिश्चित करने के लिए दोनों योजनाओं के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये का संयुक्त कुल बजट आवंटित किया गया।

3. UIDAI ने आधार सुरक्षा और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए संयुक्त अनुसंधान एवं विकास हेतु ISI के साथ 5-वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) के साथ एक पाँच-वर्षीय अम्ब्रेला समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य उन्नत अनुसंधान और विकास (R&D) पहलों के माध्यम से आधार की सुरक्षा, विश्वसनीयता और मजबूती को बढ़ाना है।

• इस समझौते पर UIDAI की उप महानिदेशक (प्रौद्योगिकी केंद्र) तनुश्री देब बर्मा और ISI के प्रमुख प्रोफेसर एस.एस. दया सागर ने UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) भावेश कुमार और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पुजिका सिंह मंडल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह उच्च-स्तरीय भागीदारी भारत के डिजिटल पहचान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इस पहल के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।

• UIDAI - ISI सहयोग का मुख्य उद्देश्य सांख्यिकीय विश्लेषण, बिग डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ISI की विशेषज्ञता का उपयोग करके आधार के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करना है। इसका उद्देश्य एक

अधिक सुरक्षित, कुशल और धोखाधड़ी-रोधी पहचान प्रणाली बनाना है जो उभरते साइबर खतरों का सामना कर सके।

• समझौते के तहत अनुसंधान में धोखाधड़ी और विसंगतियों का पता लगाने वाले तंत्र, बायोमेट्रिक सक्रियता पहचान उपकरण, उच्च जोखिम वाले नामांकन और अद्यतन श्रेणियों की पहचान, और बायोमेट्रिक मिलान एल्गोरिदम में सुधार शामिल होंगे। इन नवाचारों का उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करते हुए आधार रिकॉर्ड की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

Key Points:-

(i) यह परियोजना UIDAI और ISI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उपकरणों और कार्यप्रणालियों को प्राथमिकता देगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि समाधान भारत के पैमाने और विविधता के अनुरूप हों। फर्जी नामांकनों का पता लगाने, प्रमाणीकरण प्रणालियों को मजबूत करने और आधार के परिचालन ढांचे के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

(ii) भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में शुरू की गई UIDAI को भारत के सभी निवासियों को एक अद्वितीय 12 अंकों की पहचान संख्या, जिसे आधार के रूप में जाना जाता है, जारी करने का अधिकार है।

(iii) यह संख्या आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के तहत बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा द्वारा समर्थित है, जिससे आधार दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक ID प्रणाली बन जाती है।

4. पश्चिम रेलवे ने 'मिशन रफ्तार' के तहत भारत का पहला 2x25 KV ट्रैक्शन सबस्टेशन चालू किया।

अगस्त 2025 में, पश्चिम रेलवे (WR) ने ट्रेन की गति और परिचालन दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी 'मिशन रफ्तार' पहल के तहत मध्य प्रदेश के रतलाम डिवीजन के नागदा-खाचरोद खंड में भारत का पहला 2x25 किलो वोल्ट (kV) इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन सफलतापूर्वक चालू किया।

• नवनिर्मित सबस्टेशन दो स्कॉट-कनेक्टेड 100 मेगा-वोल्ट-एम्पीयर (MVA) पावर ट्रांसफार्मरों से सुसज्जित है, जो ओवरहेड उपकरण (OHE) को कुशलतापूर्वक विद्युत भार प्रदान करने और विश्वसनीय कर्षण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

• इस परियोजना को रतलाम की डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टीम, पश्चिम रेलवे के निर्माण विभाग, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन (TRD) टीम और मेसर्स BNC पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा तकनीकी निष्पादन में समन्वित प्रयासों का प्रदर्शन करते हुए सहयोगात्मक रूप से निष्पादित किया गया।

Key Points:-

(i) 2x25 KV प्रणाली से ऊर्जा दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि, कर्षण शक्ति की उपलब्धता में वृद्धि, तथा ट्रेन परिचालन की गति में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे यात्री और माल परिचालन के बेहतर प्रदर्शन में योगदान मिलेगा।

(ii) भारतीय रेलवे द्वारा 2016-17 के रेल बजट में 'मिशन रफ्तार' की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य मालगाड़ियों की औसत गति को बढ़ाना और देश भर में तेज, अधिक कुशल परिवहन सेवाओं के लिए रेलवे के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना था।

INTERNATIONAL

1. भारत और सिंगापुर ने तीसरे मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया।

अगस्त 2025 में, भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा और उसे आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में तीसरे भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन (ISMR) की मेजबानी की। इस बैठक में व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- **भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल थे।**

- **सिंगापुर का प्रतिनिधित्व उप प्रधानमंत्री गान किम योंग, विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन, गृह मंत्री के. षणमुगम और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों ने किया।**

Key Points:-

(i) सितंबर 2022 में शुरू किया गया ISMR उच्च-स्तरीय संवाद के लिए एक संरचित मंच के रूप में कार्य करता है। पहला दौर नई दिल्ली में, दूसरा अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था, और इस तीसरे संस्करण ने 2025 में इस गति को जारी रखा।

(ii) चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी शामिल थे। दोनों पक्षों ने वित्तीय प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

(iii) इस बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मनाई गई और सितंबर 2025 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2. भारत ने एक्ट ईस्ट नीति के तहत मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 टन लोबिया के बीज भेजे।

क्षेत्रीय एकजुटता के एक उल्लेखनीय कार्य में, भारत ने जुलाई 2025 में फिजी को पांच मीट्रिक टन काली आंखों वाले लोबिया के बीज भेजे। सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के तहत भेजी गई इस मानवीय सहायता का उद्देश्य प्रशांत द्वीप राष्ट्र में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है।

• यह खेप भारत से फिजी को भेजी गई मानवीय सहायता की पहली खेप है जिसमें लोबिया के बीज शामिल हैं। ये बीज 26 जुलाई 2025 को नई दिल्ली से रवाना हुए और सुवा स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा नाडी के पास सबेटो में फिजी सरकार को आधिकारिक रूप से सौंप दिए गए।

• इस सहायता का लक्ष्य फ़िजी में कृषि लचीलापन और खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करना है। काली आँखों वाले लोबिया के बीज अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मूल्यवान हैं—ये मनुष्यों के लिए पौष्टिक भोजन, पशुओं के लिए पौष्टिक चारे के रूप में काम करते हैं, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए आवरण फसलों के रूप में भी काम करते हैं।

• यह पहल भारत की अपने हिंद-प्रशांत साझेदारों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, और फिजी जैसे छोटे द्वीपीय देशों द्वारा सामना की जा रही जलवायु और आर्थिक कमज़ोरियों के बीच एकजुटता प्रदर्शित करती है। यह पहल स्वास्थ्य, शिक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एक सहायक विकास साझेदार के रूप में भारत की भूमिका का उदाहरण है।

Key Points:-

(i) भारत-फिजी संबंधों का इतिहास बहुत पुराना है, जिसकी शुरुआत 1879 में गिरमिटिया भारतीय मजदूरों के आगमन से हुई। प्रधानमंत्री मोदी की 2014 की फिजी यात्रा के दौरान शुरू किए गए भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग मंच (FIPIC) के तहत सहयोग के माध्यम से यह साझेदारी और मजबूत हुई।

(ii) काली आँखों वाले लोबिया के बीज बहुउद्देशीय होते हैं। ये नाइट्रोजन को स्थिर करने, मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करने और हरी खाद के रूप में काम करने में मदद करते हैं, जिससे टिकाऊ कृषि पद्धतियों में योगदान मिलता है - जो फिजी के कृषि उत्पादन और पर्यावरणीय लचीलेपन में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

BANKING & FINANCE

1. PPSL को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की मंजूरी मिली।

अगस्त 2025 में, वन97 कम्युनिकेशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (PSS अधिनियम), 2007 के तहत ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (PA) के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 'सैद्धांतिक' मंजूरी मिली। यह मंजूरी PPSL को नियामक दिशानिर्देशों के अनुपालन में परिचालन फिर से शुरू करने में सक्षम बनाती है।

• RBI की मंजूरी के लिए PPSL को 17 मार्च, 2020 को जारी और 31 मार्च, 2021 को अद्यतन किए गए भुगतान एग्रीगेटर्स और भुगतान गेटवे के विनियमन पर दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें परिचालन मानकों, सुरक्षा आवश्यकताओं और ग्राहक सुरक्षा उपायों का अनुपालन शामिल है।

Key Points:-

(i) इस मंजूरी के साथ, PPSL नए व्यापारियों को फिर से शामिल कर सकता है - एक ऐसी प्रक्रिया जो एक साल से अधिक समय से रुकी हुई थी। इस कदम

से व्यापारियों के लिए सुगम और तेज़ एकीकरण को सक्षम बनाकर डिजिटल भुगतान क्षेत्र में पेटीएम की स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद है।

(ii) RBI ने PPSL को छह महीने के भीतर साइबर सुरक्षा समीक्षा सहित एक संपूर्ण सिस्टम ऑडिट पूरा करने का निर्देश दिया है। ऑडिट के परिणाम आरबीआई को प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा सैद्धांतिक मंज़ूरी वापस ली जा सकती है। PPSL को अपनी शेयरधारिता या स्वामित्व संरचना में किसी भी बदलाव के लिए RBI की पूर्व सहमति भी लेनी होगी।

ECONOMY & BUSINESS

1. हिंदुस्तान जिंक अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद (ICMM) में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई।

अगस्त 2025 में, भारत की एकमात्र और दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत जस्ता उत्पादक कंपनी, हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (HZL), अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद (ICMM) में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनकर इतिहास रच देगी। लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK) में मुख्यालय वाली ICMM एक अग्रणी वैश्विक उद्योग निकाय है जो खनन और धातु क्षेत्र में सतत विकास, नैतिक प्रथाओं और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को बढ़ावा देती है।

● हिंदुस्तान ज़िंक का ICMM में शामिल होना भारत के खनन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यह देश को अंतरराष्ट्रीय खनन मानकों को आकार देने वाली 25 वैश्विक खनन और धातु कंपनियों के चुनिंदा समूह में शामिल करता है। 2021 में स्वीडिश कंपनी बोलिडेन के शामिल होने के बाद से यह ICMM का पहला नया सदस्य है, जो समूह की विशिष्टता को दर्शाता है।

● 2001 में स्थापित ICMM, खनन मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। सदस्य ज़िम्मेदार खनन प्रथाओं, संचालन में पारदर्शिता, जैव विविधता के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के साथ सार्थक जुड़ाव के लिए प्रतिबद्ध हैं।

● ICMM की सदस्यता के लिए चयन प्रक्रिया कठोर है। हिंदुस्तान ज़िंक की ICMM के स्वतंत्र विशेषज्ञ समीक्षा पैनल (IERP) द्वारा विस्तृत समीक्षा की गई, जिसने अनुमोदन प्रदान करने से पहले टिकाऊ खनन ढाँचों, नैतिक शासन संरचनाओं, सुरक्षा मानकों और जलवायु परिवर्तन संबंधी पहलों के अनुपालन का आकलन किया।

Key Points:-

(i) अपनी सदस्यता दायित्वों के भाग के रूप में, HZL अब पर्यावरण प्रबंधन, सामुदायिक विकास, व्यावसायिक सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन शमन और कॉर्पोरेट प्रशासन को कवर करते हुए 40 ICMM प्रदर्शन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करेगा।

(ii) यह कदम हिंदुस्तान जिंक को टिकाऊ और जिम्मेदार खनन पर वैश्विक बातचीत में भारत के लिए एक प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करता है।

2. NSO रिपोर्ट: भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में 8 साल के निचले स्तर 1.55% पर पहुंच गई।

12 अगस्त, 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने घोषणा की कि ग्रामीण, शहरी और संयुक्त आंकड़ों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापी गई भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में घटकर 1.55% हो जाएगी, जो आठ वर्षों में इसका सबसे निचला स्तर है।

• खुदरा मुद्रास्फीति में यह महत्वपूर्ण गिरावट जून 2017 के बाद से सबसे कम साल-दर-साल (YoY) दर को दर्शाती है। यह गिरावट उल्लेखनीय है क्योंकि यह लगातार छह महीनों की प्रवृत्ति को जारी रखती है जहां मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मध्यम अवधि के लक्ष्य 4% से नीचे रही है।

• NSO की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2025 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में जून 2025 में दर्ज 2.10% मुद्रास्फीति दर से काफी कमी देखी गई। विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों में लगातार नरमी ने इस ऐतिहासिक निचले स्तर में योगदान दिया।

Key Points:-

(i) खुदरा मुद्रास्फीति का एक प्रमुख घटक खाद्य मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में तेजी से गिरकर 1.76% हो गई। यह जनवरी 2019 के बाद से दर्ज की गई सबसे कम खाद्य मुद्रास्फीति है। शहरी खाद्य मुद्रास्फीति 1.74% रही, जबकि ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति थोड़ी अधिक 1.90% रही, जो दोनों क्षेत्रों में कीमतों में कमी का संकेत है।

(ii) जुलाई 2025 में ग्रामीण क्षेत्र की समग्र शीर्ष मुद्रास्फीति दर 1.18% दर्ज की गई, जबकि शहरी क्षेत्र में तीव्र गिरावट देखी गई, और मुद्रास्फीति दर घटकर 2.05% रह गई। यह अंतर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अलग-अलग उपभोग पैटर्न और बाज़ार की गतिशीलता को दर्शाता है।

(iii) मुद्रास्फीति में गिरावट से उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है और यह आने वाले महीनों में मौद्रिक नीति निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। मुद्रास्फीति के RBI के लक्ष्य सीमा के भीतर रहने के साथ, घरेलू मांग को और बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन और उपायों की संभावना है।

MOUs and Agreement

1. IFSC शिक्षा को मजबूत करने और फिनटेक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए GIFT सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

अगस्त 2025 में, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC), गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT सिटी) ने IFSC से संबंधित शिक्षा, फिनटेक नवाचार और अनुसंधान पहलों को आगे बढ़ाने के लिए गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर

हस्ताक्षर किए। यह उपलब्धि शैक्षणिक विशेषज्ञता और उद्योग क्षमता के रणनीतिक मिलन का प्रतीक है।

- **GIFT सिटी और GTU संयुक्त रूप से विशिष्ट शैक्षणिक पेशकश विकसित करेंगे, जिसमें IFSC परिचालन और डिजिटल वित्त और वित्तीय विनियमन जैसे ट्रेंडिंग फिनटेक डोमेन पर केंद्रित टेलर-मेड पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन मॉड्यूल शामिल होंगे।**

- **IFSC और वित्तीय प्रौद्योगिकी में प्रतिभा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह अनुसंधान, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक जुड़ाव के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो GIFT IFSC की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।**

Key Points:-

(i) दोनों संस्थानों के नेतृत्व ने सहयोग के पीछे की रणनीतिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला। GIFT सिटी के MD और ग्रुप CEO, संजय कौल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह साझेदारी भविष्य के लिए तैयार प्रतिभाओं का एक ऐसा समूह तैयार करने में मदद करेगी जो वैश्विक वित्तीय-तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मज़बूत कर सके, जबकि GTU की कुलपति डॉ. राजुल के. गज्जर ने शिक्षार्थियों को "वैश्विक वित्तीय बाज़ारों और तकनीकों का बेजोड़ अनुभव" प्रदान करने की बात कही।

(ii) यह साझेदारी फिनटेक और IFSC पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर शिक्षा, अनुसंधान और औद्योगिक मांगों को संरेखित करके गुजरात को एक वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सीसीआई महासचिव का पद बरकरार रखा।

13 अगस्त, 2025 को, वरिष्ठ भाजपा नेता और सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (CCI) के सचिव (प्रशासन) के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया, जो प्रभावी रूप से महासचिव है, तथा उन्होंने साथी भाजपा सांसद संजीव कुमार बालियान के साथ कड़े मुकाबले के बाद इस भूमिका में अपने अभूतपूर्व 25 वर्षों के नेतृत्व को आगे बढ़ाया।

- **चुनाव में दो वरिष्ठ भाजपा नेताओं के बीच एक दुर्लभ अंतर्दलीय टकराव देखने को मिला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता बालियान को जहाँ विभिन्न दलों और क्षेत्रीय समूहों का समर्थन मिला, वहीं रूडी ने विपक्षी सांसदों और भाजपा के भीतर के कुछ वर्गों के गठबंधन पर भरोसा जताया। इससे दांव और बढ़ गया और सामान्य चुनावी प्रक्रिया एक हाई-प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाई में बदल गई।**

- **12 अगस्त को हुआ मतदान काफी गहन और लंबा था—25 राउंड की मतगणना तक। रूडी ने 354 प्रत्यक्ष मत और 38 अतिरिक्त डाक मतपत्र हासिल करके बाल्यान को 102 मतों के अंतर से हराया।**

• इस मुकाबले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अमित शाह, जे.पी. नड्डा जैसे भाजपा के दिग्गज नेताओं और सोनिया गांधी तथा मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस नेताओं सहित विभिन्न दलों के दिग्गज वोट देने के लिए उमड़ पड़े। नतीजों ने क्लब के सत्ता समीकरण में रूडी की गहरी भूमिका की पुष्टि की।

Key Points:-

(i) संविधान सभा के सदस्यों की सेवा के लिए फरवरी 1947 में स्थापित, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, वर्तमान और पूर्व सांसदों के बीच बातचीत का एक प्रमुख मंच है। वर्षों से, यह राजनीतिक नेटवर्किंग का एक प्रतिष्ठित केंद्र बन गया है। रूडी का निरंतर नेतृत्व इस विशिष्ट संस्था में उनके विश्वास और प्रभाव को दर्शाता है।

(ii) सचिव (प्रशासन) पद के अलावा, अन्य प्रमुख पदों पर भी सुचारू रूप से बदलाव हुए। तिरुचि शिवा और राजीव शुक्ला संस्कृति एवं खेल सचिव चुने गए, जबकि ए. पी. जितेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष बने। क्लब की संचालन परिषद में प्रमुख सांसद शामिल हैं, जिससे इसका राजनीतिक प्रभाव और भी मज़बूत हुआ है।

IMPORTANT DAYS

1. विश्व अंगदान दिवस 2025 विश्व स्तर पर 13 अगस्त को "आह्वान का उत्तर देना" विषय के साथ मनाया गया।

विश्व अंगदान दिवस 2025 - 13 अगस्त को दुनिया भर में मनाया गया, जो 1954 में हुए पहले सफल अंग प्रत्यारोपण की याद में मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वैच्छिक प्रतिज्ञाओं को प्रोत्साहित करना और जीवन रक्षक प्रत्यारोपण को बढ़ावा देना है।

• विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को दुनिया भर में चिकित्सा इतिहास में हुई इस सफलता के सम्मान में मनाया जाता है - 1954 में किया गया पहला सफल जीवित दाता किडनी प्रत्यारोपण। यह दिवस प्रत्यारोपण के लिए अंगों की वैश्विक कमी को दूर करने के लिए अंगदान में सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देता है।

• 2025 का विषय, "आह्वान का उत्तर", अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती माँग को पूरा करने की तात्कालिकता और जीवन बचाने में व्यक्तियों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह अंगदान की प्रक्रिया से जुड़े मिथकों और कलंक को दूर करने का भी आह्वान करता है।

• दुनिया का पहला सफल जीवित दाता गुर्दा प्रत्यारोपण 1954 में अमेरिकी सर्जन डॉ. जोसेफ ई. मरे और उनके सहयोगियों द्वारा बोस्टन, मैसाचुसेट्स, अमेरिका स्थित पीटर बेंट ब्रिघम अस्पताल (अब ब्रिघम एंड विमेन्स हॉस्पिटल) में किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने

आधुनिक प्रत्यारोपण चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त किया।

Key Points:-

(i) इस अग्रणी प्रत्यारोपण में समान जुड़वां, रोनाल्ड और रिचर्ड ली हेरिक शामिल थे। रोनाल्ड ने अपनी एक किडनी रिचर्ड को दान कर दी, जो क्रोनिक किडनी फेल्योर से पीड़ित थे। समान जुड़वाँ बच्चों के बीच आनुवंशिक मिलान ने उस युग में अंग अस्वीकृति के जोखिम को कम करने में मदद की।

(ii) डॉ. जोसेफ ई. मरे को अमेरिकी चिकित्सक ई. डोनल थॉमस के साथ मिलकर 1990 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अंग और कोशिका प्रत्यारोपण में अभूतपूर्व खोज की थी, जिससे विश्व स्तर पर लाखों लोगों की जान बच गई।

(iii) अंगदान स्वास्थ्य सेवा की एक अहम ज़रूरत बनी हुई है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट के अनुसार हर साल हज़ारों लोग प्रत्यारोपण के इंतज़ार में मर जाते हैं। विश्व अंगदान दिवस जैसे आयोजनों का उद्देश्य दाता पंजीकरण को बढ़ावा देना और दुनिया भर में नैतिक और समान अंग वितरण के लिए नीतिगत ढाँचों को मज़बूत करना है।

2. अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस 2025 विश्व स्तर पर 13 अगस्त को मनाया गया।

13 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट-हैंडर्स दिवस 2025 मनाया गया ताकि बाएँ हाथ से काम करने वालों की विशिष्टता, लाभ और हानि का जश्न मनाया जा सके। यह दिन बाएँ हाथ से काम करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है और उत्पाद डिज़ाइन, शिक्षा और कार्यस्थलों में समावेशिता को बढ़ावा देता है।

• अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है ताकि दुनिया की लगभग 10% आबादी जो बाएँ हाथ से काम करती है, को सम्मानित किया जा सके। इसका उद्देश्य उनकी अनूठी क्षमताओं के बारे में जागरूकता फैलाना और मुख्यतः दाएँ हाथ से काम करने वाले लोगों की दुनिया में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करना है।

• अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस पहली बार 13 अगस्त, 1976 को मनाया गया था, जिसकी शुरुआत लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल के संस्थापक डीन आर. कैंपबेल ने की थी। इस दिन को वैश्विक मान्यता 1992 में मिली जब लेफ्ट हैंडर्स इंटरनेशनल ने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस की शुरुआत की।

• वैज्ञानिक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बाएँ हाथ का होना कुछ हद तक आनुवंशिक है, और इस भिन्नता के लगभग 25% के लिए आनुवंशिक कारक ज़िम्मेदार हैं। अन्य प्रभावों में जन्मपूर्व स्थितियाँ, जन्म संबंधी जटिलताएँ और पर्यावरणीय कारक शामिल हैं। जीनोम-व्यापी संबद्धता अध्ययनों (GWAS) ने बाएँ हाथ के होने से जुड़े कई जीनों की पहचान की है।

Key Points:-

(i) एक दुर्लभ आनुवंशिक प्रकार, TUBB4B (ट्यूबुलिन बीटा 4B क्लास IVb), को बाएं हाथ से काम करने वालों से जोड़ा गया है। यह प्रकार बाएं हाथ से काम करने वालों में लगभग 2.7 गुना ज़्यादा

आम है, लेकिन आबादी के केवल 0.1% लोगों में ही मौजूद है, जिससे यह एक दुर्लभ घटना बन जाती है।

(ii) मस्तिष्क के गोलार्ध हाथ के उपयोग में भूमिका निभाते हैं: दायाँ गोलार्ध आमतौर पर बाएँ हाथ को नियंत्रित करता है, जबकि बायाँ गोलार्ध दाएँ हाथ को नियंत्रित करता है। बाएँ हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों में, मोटर नियंत्रण का प्रभुत्व दाएँ हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की तुलना में उलट होता है।

(iii) (iii) अध्ययनों में पाया गया है कि बाएं हाथ के लोगों में कुछ मानसिक रोग संबंधी लक्षणों, जैसे सिज़ोफ्रेनिया और ऑटिज़्म का अधिक जोखिम हो सकता है। इसके अतिरिक्त, साइनिस्ट्रोफोबिया (Sinistrophobia) का अर्थ है बाएं हाथ के प्रयोग या शरीर के बाईं ओर से संबंधित किसी भी चीज़ का भय या नापसंद।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. पिक्सेलस्पेस इंडिया-नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को PPP मॉडल के तहत भारत के पहले स्वदेशी वाणिज्यिक EO उपग्रह तारामंडल को लॉन्च करने के लिए चुना गया।

अगस्त 2025 में, अंतरिक्ष विभाग (DoS) के अंतर्गत कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने घोषणा की कि पिक्सेलस्पेस इंडिया (PSI), पियरसाइट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, सैटस्योर एनालिटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के एक संघ का नेतृत्व करेगा, जो भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक भू-अवलोकन (EO) उपग्रह समूह का विकास और संचालन करेगा। ₹1,200 करोड़ से अधिक मूल्य की यह परियोजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) ढांचे के तहत क्रियान्वित की जाएगी।

- **पिक्सेलस्पेस इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को 12 उन्नत EO उपग्रहों के एक समूह को प्रक्षेपित करने और प्रबंधित करने का कार्य सौंपा गया है। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में एक मील का पत्थर है क्योंकि यह अपनी तरह की पहली निजी कंसोर्टियम-नेतृत्व वाली पहल है, जो स्वदेशी उपग्रह क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कई घरेलू अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्मों की क्षमताओं को जोड़ती है।**

- **इस परियोजना में कुल निवेश ₹1,200 करोड़ से अधिक है और यह अगले पाँच वर्षों में पूरा होगा। EO उपग्रहों को चरणबद्ध तरीके से तैनात किया जाएगा ताकि निरंतर तकनीकी उन्नयन, विस्तारित भौगोलिक कवरेज और वाणिज्यिक एवं सरकारी अनुप्रयोगों के लिए बेहतर डेटा विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।**

- **PPP ढांचे के तहत, IN-SPACe और भारत सरकार कंसोर्टियम को रणनीतिक, तकनीकी और नीतिगत स्तर का समर्थन प्रदान करेंगे। यह कंसोर्टियम उपग्रह निर्माण, प्रक्षेपण, संचालन और व्यावसायीकरण का काम संभालेगा, और सरकार की भागीदारी राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति के उद्देश्यों और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।**

Key Points:-

(i) यह तारामंडल अत्याधुनिक पेलोड से सुसज्जित होगा, जिसमें पैनक्रोमैटिक, मल्टी-स्पेक्ट्रल, हाइपरस्पेक्ट्रल और माइक्रोवेव सिंथेटिक अपर्चर

रडार (SAR) सेंसर शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ विभिन्न मौसम स्थितियों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन, दिन-रात इमेजिंग क्षमताएँ प्रदान करेंगी, और रक्षा, सुरक्षा और संसाधन निगरानी में महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का समर्थन करेंगी।

(ii) इस समूह से प्राप्त डेटा जलवायु परिवर्तन निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि, शहरी नियोजन, समुद्री सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए विश्लेषण-तैयार डेटा (ARD) और मूल्य-वर्धित सेवाएँ (VAS) प्रदान करेगा। यह पहल विदेशी ईओ डेटा स्रोतों पर निर्भरता कम करके वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत करती है।

(iii) इस परियोजना का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना है, सरकार का लक्ष्य 2022 में 8.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2033 तक 44 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचना है। तारामंडल की उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली इमेजरी भारत की विदेश नीति, संप्रभुता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक निर्णय लेने में भी सहायता करेगी।

2. एरियनस्पेस के एरियन 6 ने फ्रेंच गुयाना के कौरू से मेटॉप-SGA1 मौसम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

अगस्त 2025 में, एरियनस्पेस ने अपने नए विकसित एरियन 6 रॉकेट का दूसरा वाणिज्यिक मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें मेटॉप-SGA1 मौसम उपग्रह को यूरोप के स्पेसपोर्ट, कूरू, फ्रेंच गयाना से प्रक्षेपित किया गया। यह मिशन फ्रांस के CSO-3 उपग्रह के साथ पहले मिशन के बाद यूरोपीय अंतरिक्ष क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

- **एरियन 6 रॉकेट, सेवानिवृत्त एरियन 5 का उत्तराधिकारी है और इसे फ्रांसीसी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता एरियनस्पेस द्वारा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency – ESA) की ओर से संचालित किया जाता है। इसे संस्थागत और वाणिज्यिक पेलोड के लिए विभिन्न प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपणों को लचीले ढंग से पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।**

- **इस मिशन में मेटॉप-SGA1 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, जो कि यूरोपीय संगठन फॉर द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites – EUMETSAT) द्वारा विकसित अगली पीढ़ी का जलवायु और मौसम निगरानी उपग्रह है। इस उपग्रह को लगभग 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट (Sun-Synchronous Orbit – SSO) में स्थापित किया गया।**

- **मेटॉप-SGA1 मौसम पूर्वानुमान और जलवायु निगरानी को बेहतर बनाएगा, जिसमें ध्रुवीय कक्षा से तापमान, वर्षा, बादलों का गठन, हवाएं, समुद्री बर्फ, एरोसोल और वायुमंडलीय प्रदूषण के उच्च-रिज़ॉल्यूशन अवलोकन उपलब्ध होंगे। यह उन्नत क्षमता मौसम वैज्ञानिकों को गंभीर मौसम और दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तनों का सटीक पता लगाने में मदद करेगी।**

Key Points:-

(i) एयरबस डिफेंस एंड स्पेस (Airbus Defence

and Space) द्वारा निर्मित इस उपग्रह में छह वायुमंडलीय साउंडिंग और इमेजिंग उपकरण मिशन लगाए गए हैं, जो ऑप्टिकल, इन्फ्रारेड और माइक्रोवेव अवलोकन एकत्र कर सकते हैं। ये आंकड़े यूरोप और दुनिया भर में परिचालन मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

(ii) मेटॉप-एसजीए1 मिशन, यूरोपीय आयोग (European Commission) के कोपरनिकस कार्यक्रम (Copernicus Programme) का हिस्सा है और वायु गुणवत्ता व ग्रीनहाउस गैस सांद्रता की निगरानी के लिए सेंटिनल-5 (Sentinel-5) उपग्रह के साथ कार्य करेगा। दोनों उपग्रह मिलकर अंतरिक्ष से पर्यावरण निगरानी में यूरोप की अग्रणी भूमिका को और मजबूत करेंगे।

(iii) 1980 में स्थापित एरियनस्पेस उपग्रहों के सभी वर्गों के लिए प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करता है और किसी भी पेलोड को किसी भी समय परिवहन करने की क्षमता रखता है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेविड कैविल्हेस (David Cavilhaes) हैं। मेटॉप-एसजीए1 के सफल प्रक्षेपण ने एरियनस्पेस की वैश्विक अंतरिक्ष परिवहन सेवाओं में अग्रणी भूमिका को पुनः सिद्ध किया है।

Static GK

RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
International Council on Mining and Metals (ICMM)	अध्यक्ष: रोहितेश धवन	मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK)
Indian National Space Promotion and Authorisation (IN-SPACE)	अध्यक्ष : पवन कुमार गोयनका	मुख्यालय :अहमदाबाद, गुजरात
Competition Commission of India	अध्यक्ष: रवनीत कौर	मुख्यालय: नई दिल्ली
Tamil Nadu	मुख्यमंत्री: एम के स्टालिन	राज्यपाल: आर. एन. रवि
Arianespace	संस्थापक: फ्रेडरिक डी'ऑलेस्ट	मुख्यालय: एवरी-कौरकोरोन्स, फ़्रांस
Fiji	प्रधान मंत्री: सितिवनी राबुका	राजधानी: सुवा
Rajasthan	मुख्यमंत्री: भजन लाल शर्मा	राज्यपाल: हरिभाऊ बागड़े
Indian Statistical Institute (ISI)	अध्यक्ष : शंकर कुमार पाल	मुख्यालय : कोलकाता (पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल)